

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग
प्रेमनगर, देहरादून

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-35/रेशम/तक0अनु0/बजट/2008-09 दिनांक 03 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या-31 (टी0एस0पी0) के आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित रू०-660.00 हजार (रू० छः लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वहन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-267/XXVII(1)/2008, दिनांक-27 मार्च, 2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/ निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिध्यादन नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 आय व्यय सम्बन्धी नियम एवं भित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/ दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 4- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- 5- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।
- 6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 7- व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।
- 8- व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

PLJ

- 9- योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा-निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- 10- लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 11- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 12- यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि आवंटित धनराशि का उपयोग जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्ययोजना भी तैयार की जाय, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
- 13- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-00-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-00 के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-77(P)/XXVII-4/2008, दिनांक-06 जून 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

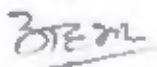
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 571/XVI/08/7(34)/08, तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग भाजरा, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
14. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

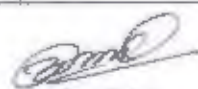
आज्ञा से,


(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-⁵⁷¹/XVI/08/7(34)/2008 दिनांक: 10 जून, 2008 का संलग्नक
 रेशम विकास विभाग की वर्ष 2008-09 की अनुदान संख्या-31 की राज्य सेक्टर की आयोजनागत
 योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का योजना/
 मदवार विवरण।

अनुदान सं०-31 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म 00-आयोजनागत 786-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-00-			
		(धनराशि हजार रु० में)	
क्र०सं०	योजना/मद	वर्ष 2008-09 हेतु प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	09-सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	100	100
2	10-जैविक रेशम विकास 02-मजदूरी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 28-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 31-सामग्री और सम्पत्ति	20 20 20 40	20 20 20 40
	योग :10-	100	100
3	11-वृक्षारोपण विकास योजना 02-मजदूरी 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 31-सामग्री और सम्पत्ति	20 20 70	20 20 70
	योग :11-	110	110
4	12-केन्द्र पोषित कैटेलेटिक योजना 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	200	200
6	17-रेशम वस्त्र विकास कार्यक्रम 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	50	50
	योग :17-	50	50
6	18-रेशम प्रशिक्षण योजना 08-कार्यालय व्यय 42-अन्य व्यय 44-प्रशिक्षण व्यय	20 50 30	20 50 30
	योग :18-	100	100
	योग,अनुदान संख्या 31 (कमाक 1 से 8 तक)	660	660

(रुपये छः लाख साठ हजार मात्र)


 (अर्जुन सिंह)
 अपर सचिव